जनसत्ता पेज 12
15.11.13

निजीकरण पर कैट ने चिंता जताई

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 14 नवंबर। केंद्र सरकार के एक फैसले में गजट अधिसूचना से माप तौल विभाग को निजी कंपनियों के हवाले करने की मंशा पर कैट ने चिंता जताई है। देश भर में किसी के भी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे माप तौल उपकरण की जांच अब निजी टेस्टिंग सेंटर करेंगे जो न केवल व्यापारियों बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक आत्मघाती कदम होगा। देश में जब भी किसी चीज का निजीकरण हुआ है लोगों को उस से राहत की जगह परेशानियों का ही सामना करना पड़ा है ।

कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया व महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्र सरकार के इस कदम को राज्य की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि देश भर में माप तोल विभाग राज्य सरकार के आधीन ही काम करते हैं। इस नाते केंद्र सरकार की यह अधिसूचना राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है। अभी तक ऐसी जांच सरकारी विभाग की विशेष जांच एजंसी किया करती थी लेकिन अब यह अधिकार सरकार ने निजी टेस्टिंग एजंसी को दे दिया है। इस प्रकार की टेस्टिंग एजंसी देश भर में कारपोरेट घरानों की ओर से चलाई जाएगी जिनमें आधुनिक उपकरण होंगे।